7. *Allegation:* It was alleged that prosecution was not filed against the company for default in T.D.S. payment.

Position: The amount of penalty was reduced to Rs. 1 lakh for assessment year 1985-86 by the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Bombay. The prosecution proceedings for assessment year—1985-86 and 1986-87 have been dropped in view of decision of ITAT and the opinion of Ministry of Law.

घरेलू मदों के उत्पादन में कमी

*135. **श्री सोमपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20 जून, 1995 के "द हिन्दू" दैनिक समाचार-पत्र में छपे उस लेख को देखा है जिसमें घरेलू उत्पादों में कमी आने और सरकार द्वारा इस संबंध में एकत्रित आंकड़ों को वास्तविकता से अधिक दिखाए जाने की बात कही गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार गिरती हुई बचत दर एवं आंकड़ों का सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय करना चाहती है?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह): (क) जी, हां। लेख का शीर्षक "क्या घरेलू बचतों को वास्तविकता से अधिक अनुमानित किया गया है?" यह लेख "घरेलू मदों के उत्पादन" के बारे में प्रकाशित हुआ प्रतीत नहीं होता। फिर भी उक्त लेख मुख्य रूप से अपने आकलन में बचतों और संबंधित कार्य प्रणाली से संबंधित मामलों को समर्पित है।

(ख) बचतों और पूंजी निर्माण के अनुमान लगाने का चालू तरीका लगभग 12 वर्ष पहले प्रो० के० एन० राज की अध्यक्षता में बचतों पर स्थापित कार्यकारी दल द्वारा सुझाई गई प्रणाली पर आधारित है। तब से बहुत से नए विकास हुए हैं। अर्थव्यवस्था में प्रमुख सुधार आरम्भ किए गए हैं। प्रयुक्त आवश्यकताओं में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए, सांख्यिकी विभाग ने विद्यमान कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और तरीकों व कार्य-प्रणालियों में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए अप्रैल, 1995 में बचत और पूंजी निर्माण पर एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है।

Non-Extension of counter guarantee for SEBs

*136. SHRI SANATANI BISI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the name of SEBs in whose favour Government have not approved the extension of counter guarantee for non-compliance of the terms and conditions; and

(b) whether total generating capacity of such SEBs is likely to be adversely affected as a result thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) Government of Inida has decided to extend Government of India (GOI) counter guarantee to eight initial projects cleared from the foreign investment angle. GOI counter guarantee documents in respect of two projects viz. Dabhol Power Project (695 MW- Phase-I) in Maharashtra and Ib Valley TPS (Unit 3 & 4—2×210 MW) in Orissa have been signed. GOI counter guarantee for other projects are under finalisaiton. So far, the issue of not extending GOI counter guarantee for the already agreed projects due to non-compliance of the terms and conditions by the concerned State Electricity Board (SEB) has not arisen.

(b) Does not arise.

Gas based Power Projects

*137. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the details of gas-based power projects in the country;